



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)  
PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 52] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1983/भाष 13, 1904  
No. 52] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 1983/MAGHA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate  
compilation

उद्योग मंत्रालय  
(औद्योगिक विकास विभाग)  
आदेश

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1983

का० आ० 82(अ)/18खख/आई०डी०आर०ए०/83 :—भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 958(अ)/18-खख/आई०डी०आर०ए०/80, तारीख 10 दिसम्बर, 1980 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है), केन्द्रीय सरकार ने, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-खख की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा की थी कि उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी संविदाओं, सम्पत्ति के हस्तान्तरण पत्रों, करारों, व्यवस्थापनों, पंजाटों, स्थायी आदेशों या अन्य लिखतों का (उनसे भिन्न जो 4 फरवरी, 1978 के पश्चात् किए गए हैं, हुए हैं या प्रवृत्त होते हैं) जिनका आश्रय प्रदेश राज्य के श्री काकुलम जिले के बोबिलो में श्री श्री के विनिर्माण में लगे मैसर्स श्री राम कृष्ण एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एकक का उक्त एकक का स्वामित्व रखने वाली कम्पनी एक पक्षकार है या जो उक्त एकक या कम्पनी को लागू हो, प्रवर्तन 3 अगस्त, 1981 तक की अवधि के लिए जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, निम्नलिखित रहेगा और उक्त आदेश के जारी किए जाने की तारीख से पूर्व उसके अधीन प्रोद्भूत या उद्भूत होने वाले सभी अधि-कार, विशेषाधिकार, बाध्यताएं और दायित्व उक्त अवधि के लिए निम्नलिखित रहेंगे;

और केन्द्रीय सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के क्रमशः आदेश सं० का० आ० 622/18-खख/आई०डी०आर०ए०/81,

तारीख 4 अगस्त 1981 और का० आ० 550(अ)/18 खख/आई०डी०आर० ए०/82 तारीख 2 अगस्त, 1982 द्वारा उक्त आदेश की अवधि सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रति प्रतिभूत दायित्व से संबंधित हैं) 3 फरवरी, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित जारी रखी गई थी ।

और केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त आदेश की अवधि सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 3 अगस्त, 1983 तक की जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की अवधि के लिए बढ़ा दी जानी चाहिए ।

अतः, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18 खख की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त आदेश की अवधि सभी मामलों की बाबत (उनसे भिन्न जो बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के प्रति प्रतिभूत दायित्वों से संबंधित हैं) 3 अगस्त, 1983 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाती है ।

[का० सं० 4(4)/78 सी०यू०एस०]

MINISTRY OF INDUSTRY  
(Department of Industrial Development)  
ORDER

New Delhi, the 2nd February, 1983

S.O. 82(E)/18FB/IDRA/83.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Develop-

ment), No. S.O. 958(E)/18FB/IDRA/80, dated the 10th December, 1980 (hereinafter referred to as the said Order), the Central Government, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), declared that the operation of all contracts, assurances of property, agreements, settlements, awards, standing orders or other instruments in force immediately before the date of issue of the said Order (other than those which have been entered into, arrived at or come into force after the 4th February, 1978), to which the unit of Messrs. Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh or the Company owning the said unit is a party or which may be applicable to the said unit or company, shall remain suspended for a period upto and inclusive of the 3rd August 1981 and all the rights, privileges, obligations and liabilities accruing or arising thereunder before the date of issue of the said order shall remain suspended for the said period;

And, whereas, by the Order of Central Government in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 622(E)/18FB/IDRA/81, dated the 4th August, 1981 and S.O. 550(E)/18FB/IDRA/82 dated the 2nd August, 1982 respectively the duration of the said Order was continued upto and inclusive of 3rd February, 1983 (in respect of all matters except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions).

And, whereas, the Central Government is satisfied that the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) should be extended for a further period of six months upto and inclusive of 3rd August, 1983:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18FB of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby extends the duration of the said Order in respect of all matters (except those relating to secured liabilities to banks and financial institutions) for a further period of six months upto and inclusive of 3rd day of August, 1983.

[File No. 4(4)/78-CUS]

#### आदेश

क्र० आ० 83(अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/83 — भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० 65 (अ)/18कक/आई०डी०आर०ए०/78 तारीख 1 फरवरी, 1978 द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) द्वारा प्रदेश राज्य के श्री कामलम जिन्हे के बाबिली में श्री विनिर्मित में लगे हुए श्री राम शर्मा एण्ड इण्डस्ट्रीज लिमिटेड एकक का (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त औद्योगिक उपक्रम कहा गया है) प्रबंध उद्योग

(विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) द्वारा 18कक की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन उक्त आदेश के राज्य में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए ग्रहण किया गया था और निजाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड का औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध उद्योग करने के लिए प्राधिकृत किया गया था।

और भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश आदेश सं० 622(अ)/901(अ), तारीख 21 नवम्बर, 1980 और क्र० आ० 619(अ), तारीख 3 अगस्त, 1981 और क्र० आ० 549(अ) तारीख 2 अगस्त, 1982 द्वारा उक्त आदेश 3 फरवरी, 1983 तक की अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, जारी रखा गया था।

और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लाकड़ में यह समीचीन है कि उक्त औद्योगिक उपक्रम निजाम शुगर फैक्टरी लिमिटेड के प्रबंध के अधीन 3 अगस्त, 1983 तक की छह मास की और अवधि के लिए, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है बना रहना चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18कक की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त आदेश 3 अगस्त, 1983 तक, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है, छह मास की और अवधि के लिए प्रभावी बना रहेगा।

[क्र० सं० 4 (4)/78-सी०ए०/एस०]

ग० पी० मन्वस, संयुक्त सचिव,

#### ORDER

**S.O. 83(E)/18AA/IDRA/83.**—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development), No. S.O. 65(E)/18AA/IDRA/78, dated the 4th February, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the unit of Messrs Sri Rama Sugars and Industries Limited manufacturing sugar at Bobbili in District Srikakulam in the State of Andhra Pradesh (hereinafter referred to as the said industrial undertaking) was taken over under clause (b) of sub-section (1) of section 18AA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), for a period of three years from the date of publication of the said Order in the Official Gazette and the Nizam Sugar Factory Limited was authorised to take over management of the said industrial undertaking :

And, whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 901(E), dated the 21st November, 1980, S.O. 619(E) dated the 3rd August, 1981 and S.O. 549(E) dated the 2nd August, 1982 respectively the said Order was continued for a period upto and inclusive of 3rd February, 1983 :

And, whereas, the Central Government is of opinion that it is expedient in the Public Interest that the said industrial undertaking should continue under the management of the Nizam Sugar Factory Limited for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd August, 1983;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 18AA of In-

dustries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period of six months upto and inclusive of the 3rd August, 1983.

[File No. 4(4)78-CUS]

A. P. SARWAN, Jt. Secy.

